



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51]
No. 51]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 31, 1985/माघ 11, 1906
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 1985/MAGHA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलन संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग तथा कंपनी कार्य मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1985

का. प्रा. 67(अ) भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. प्रा.
387 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1979 सं. का. प्रा.
497 (अ) तारीख 5 जुलाई, 1980 सं. का. प्रा.
541 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1981 सं. का. प्रा. 480
(अ) तारीख 7 जुलाई 1982 सं. का. प्रा. 497 (अ),
तारीख 7 जुलाई 1983 सं. का. प्रा. 489 (अ) तारीख
6 जुलाई, 1984 तथा सं. का. प्रा. 983 (अ) तारीख
31 दिसम्बर 1984 के साथ पठित भारत सरकार के भूत-
पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. प्रा.
426 (अ) तारीख 8 जुलाई 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके
पश्चात उक्त आदेश कहा गया है), में एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज
(ग्रसम) लिमिटेड, चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के
रसायन एकक का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन)

अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क
की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के अधीन 31 जनवरी,
1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए
ग्रहण कर लिया गया था और मे० ग्रसम इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट
कारपोरेशन लि. को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध
ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित
में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध
में ग्रसम इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के पास 31
मार्च 1985 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहे,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की
उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रयोग करते हुए
यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1985 तक,
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

[सं. 4 (4) / 80 सी. यू.एस]

ए. पी. संवरन, संयुक्त सचिव,।

**MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY
AFFAIRS**

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st January, 1985

S. O. 67(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426(E), dated the 8th July, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Nos. S.O. 387(E), dated the 7th July, 1979, S.O. 497(E), dated the 5th July, 1980, S.O. 541(E), dated the 6th July, 1981, S.O. 480(E), dated the 7th July, 1982, S.O. 497(E), dated the 7th July, 1983, S.O. 489(E), dated the 6th July, 1984 and S.O. 983(E), dated the 31st December, 1984, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur, was taken over under

clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) upto and inclusive of the 31st January, 1985, and Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And Whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue to be under the management of Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited upto and inclusive of 31st March, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect upto and inclusive of the 31st March, 1985.

INo. 4(4)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.